69 फीसद प्रबंधकों का काम 2024 तक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) के जरिये होने लगेगा। यह दावा अनुसंधान और सलाहकार फर्म गार्टनर इंक ने एक शोध के बाद की है।

बोल्सोनारो आए, गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे

नई दिल्ली, प्रेट्र : ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर मेसियस बोल्सोनारो शुक्रवार को चार दिनों की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए। उनकी शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उच्च स्तरीय वार्ता होगी। वार्ता के बाद दोनों देशों के सहयोग के 15 समझौतों पर दस्तखत किए जाएंगे। राष्ट्रपति बोल्सोनारो राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर राष्ट्रपति बोल्सोनारो के भारत आगमन का स्वागत किया है। उम्मीद जताई है कि उनकी यात्रा से दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाइयां छुएंगे।

बोल्सोनारो के साथ उनकी बेटी लौरा बोल्सोनारो, पुत्रवधू लेतीसिया फर्मो, आठ मंत्री, ब्राजीली संसद के चार सदस्य और एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया हुआ है। उच्च स्तरीय वार्ता के बाद तेल व गैस, खनन, स्वास्थ्य और साइबर सिक्युरिटी समेत 15 समझौतों पर दस्तखत होंगे। मोदी और बोल्सोनारो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत बनाने पर विचार करेंगे। मंदी के दौर से गुजर रहे दोनों देश आपस में व्यापार और सहयोग बढ़ाकर आर्थिक सक्रियता बढ़ाने पर भी विचार करेंगे। नई दिल्ली आने के कुछ घंटों बाद बोल्सोनारो अपने कुछ अधिकारियों के साथ अक्षरधाम मंदिर देखने गए।

ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर मेसियस बोल्सोनारो चार दिन की भारत यात्रा पर शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे। एपी

ब्राजील लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शुमार ब्राजील की आबादी 21 करोड़ है और उसकी अर्थव्यवस्था 1.8 ट्रिलियन डॉलर (126 लाख करोड़ रुपये) है। विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) विजय ठाकुर सिंह ने कहा है कि राष्ट्रपति बोल्सोनारो की भारत यात्रा बहुत महत्व वाली है। यह दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में फिर से जान फूंकने वाली होगी। बोल्सोनारो की यह पहली भारत यात्रा है। ब्राजीली सेना के पूर्व कैप्टन बोल्सोनारो ने अपने देश में अक्टूबर 2018 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। इसके बाद जनवरी 2019 में उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला।

बच्चे अपने अधिकारों के बजाय दायित्वों को अधिक अहमियत दें : पीएम

मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता बच्चों से कहा, मुझे आपसे प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है

नई दिल्ली, एजेंसियां : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बच्चों के कार्यों की सराहना की और कहा कि युवा साथियों के ऐसे साहसिक काम के बारे में सुनने से उन्हें प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। उन्होंने पुरस्कृत बच्चों से आग्रह किया कि वह अपने अधिकारों के बजाय अपने दायित्वों को अधिक अहमियत दें।

मोदी ने शुक्रवार को अपने आवास पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 के 49 बाल विजेताओं से बातचीत में कहा, 'हमें अपने कर्तव्यों को वरीयता देनी चाहिए। हम कब तक अपने अधिकारों पर ही ध्यान देंगे? मुझे इस बात पर गर्व है कि आप समाज और देश के प्रति अपने दायित्वों के प्रति सजग हैं।' उन्होंने कहा, 'थोड़ी देर पहले आप सभी का परिचय जब हो रहा था, तब मैं सच में हैरान था। इतनी कम आयु में जिस प्रकार आप सभी ने अलग-अलग क्षेत्रों में जो प्रयास किए, जो काम किया है, वो अद्भुत है।' उन्होंने कहा कि आप अपने समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और अपने कर्तव्य पालन के लिए जिस प्रकार से जागरूक हैं, यह देखकर गर्व होता है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'मैं आप सभी युवा साथियों के ऐसे साहसिक काम के बारे में जब भी सुनता हूं, आपसे बातचीत करता हूं, तो मुझे भी प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुक्रवार को अपने आवास पर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बच्चों ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने बच्चों का हौसला बढ़ाया। एएनआइ

पुलिस का आदर करना चाहिए : उन्होंने होनहार बच्चों को बताया कि आजादी के बाद से लोगों की सुरक्षा के लिए 33 हजार पुलिस कर्मी अपने प्राणों का बलिदान कर चुके हैं। हमें उनका आदर करना चाहिए। कई बार लोग पुलिस वालों को पसंद नहीं करते क्योंकि वह उन्हें साइकिल या अन्य वाहन सही से चलाने को कहते हैं। उन्होंने बच्चों को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जाने के लिए प्रेरित किया।

पीएम के चेहरे की चमक का राज! : मोदी ने बच्चों को बताया कि बहुत साल पहले किसी ने उनसे पूछा था कि उनके चमकते चेहरे का राज क्या है? उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा, 'मैं बहुत मेहनत करता हूं और मुझे बहुत पसीना होता है। मैं वह पसीना पोंछता हूं तो चेहरा चमक जाता है।' उन्होंने बच्चों से कहा कि वह औरों को भी बोलें कि कोई बच्चा ऐसा रहने ना पाए जिसे दिन में चार बार खूब पसीना ना हो।

साफ पानी व जूस पीने की सलाह : : मोदी ने बच्चों को स्वच्छ पेयजल तथा जूस पीने की सलाह दी और शारीरिक दृष्टि से सक्रिय रहने का भी सुझाव दिया ताकि उन्हें (बच्चों को) दवा नहीं खाना पड़े। इस बातचीत के दौरान एक विजेता बच्चे हृदयनारायण सिंह भाटी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित हुआ हैं और उसने उनसे देश के लिए काम करना सीखा है। भाटी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सर मैंने आपसे सीखा है कि अगर देश आपको कुछ देता है तो आपको भी किसी न किसी रूप में देश को कुछ देना होगा।

कश्मीर, मणिपुर, अरुणाचल के भी बच्चे : ये 49 पुरस्कृत बच्चे देश के विभिन्न राज्यों के हैं, जिनमें एक-एक पुरस्कृत बच्चा जम्मू कश्मीर, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश का भी है। इन बच्चों ने कला एवं संस्कृति, नवाचार, प्रतिभा,समाज सेवा, खेल और बहादुरी जैसे क्षेत्रों में पुरस्कार हासिल किया है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं में 12 वर्षीय दर्श मलानी भी शामिल हैं जिन्होंने दुनिया भर में 50 मैजिक शो किए हैं और इसमें 11 वर्षीय मनोज कुमार लोहार भी शामिल है जिन्होंने तबला वादन में महारत हासिल की है।

न्यूज गैलरी

देश के नाम राष्ट्रपति का संबोधन आज शाम सात बजे

नई दिल्ली : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 71वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शनिवार को देश को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान के मुताबिक, 'राष्ट्रपति के संबोधन का शाम सात बजे हिंदी में ऑल इंडिया रेडियो (एआइआर) के पूरे नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारण किया जाएगा। इसके बाद उनके संबोधन के अंग्रेजी संस्करण का प्रसारण किया जाएगा।' हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर राष्ट्रपति के संबोधन का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। एआइआर पर संबोधन को क्षेत्रीय भाषा में रात 9 .30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। (प्रेट्र)

भूषण स्टील के पूर्व सीएमडी सिंघल को मिली जमानत

नई दिल्ली : भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड के पूर्व सीएमडी (मुख्य प्रबंध निदेशक) संजय सिंघल की जमानत अर्जी को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने मंजूर कर लिया है। 10 लाख के मुचलके और दो गारंटी पर उनको जमानत मिली है। उन्हें पासपोर्ट भी जमा कराना होगा। इसी सप्ताह ईडी ने हजारों करोड़ के बैंक लोन घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें सिंघल को मास्टरमाइंड बताया गया है। ईडी ने 22 नवंबर 2019 को सिंघल को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि 2007 से 2014 के बीच 33 बैंक और वित्तीय संस्थानों से लोन लिए गए। 30 जनवरी 2018 तक 47 हजार 204 करोड़ की रकम बकाया थी। बैंकों से पैसा लेकर उसे धोखे से अलग-अलग खातों में डायवर्ट किया गया था। (जासं)

डीजीसीए ने तनेजा एयरोस्पेस के पायलट को निलंबित किया

नई दिल्ली : डीजीसीए ने शुक्रवार को कहा कि उसने तनेजा एयरोस्पेस के सेसना विमान के पायलटों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया है। पिछले वर्ष पायलटों ने नांदेड़ हवाई अड्डे पर रनवे का उल्लंघन किया था। तनेजा एयरोस्पेस कारपोरेट सेक्टर के लिए चार्टर सेवा मुहैया कराता है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) की जांच में पाया गया कि एयर ट्राफिक कंट्रोल ने पिछले वर्ष 11 सितंबर को पायलटों को रनवे संख्या 28 पर अपना विमान उतारने की अनुमति दी थी, लेकिन उन्होंने इसकी जगह रनवे संख्या 10 पर विमान को उतारा। इस रनवे पर रोशनी प्रणाली काम नहीं कर रही थी। इससे विमान को नुकसान पहुंचा। (प्रेट्र)

रासुका का इस्तेमाल नहीं करने का व्यापक आदेश नहीं दे सकते : कोर्ट

स्पष्ट रुख ▶ शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को संशोधित याचिका दाखिल करने की छूट दी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली व अन्य राज्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के प्रावधान लागू किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन्कार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा, रासुका का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके इस्तेमाल पर रोक का व्यापक आदेश जारी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक संपत्तियां जलाई जा रही हैं ये संगठित भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस पर रोक का व्यापक आदेश नहीं दे सकता इससे अफरातफरी मच सकती है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप विशिष्ट घटना बताइए जिसमें इसका दुरुपयोग हुआ हो। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इन्कार करते हुए याचिकाकर्ता को संशोधित याचिका दाखिल करने की छूट देते हुए याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा

- रासुका का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पर रोक का व्यापक आदेश नहीं दिया जा सकता इससे अफरातफरी मच सकती है
- क्या याचिकाकर्ता को नहीं पता कि कोलकाता, त्रिपुरा और असम में क्या हो रहा है। संपत्तियां जलाई जा रही हैं, ये संगठित हो सकता है। हमें लोगों की पृष्ठभूमि नहीं मालूम

वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों पर रासुका के इस्तेमाल की आशंका जताई थी और दिल्ली सहित कुछ प्रदेशों में रासुका लागू करने की अधिसूचना को चुनौती दी थी।

जस्टिस अरुण मिश्रा और इंद्रा बनर्जी की पीठ के समक्ष याचिका पर बहस करते हुए शर्मा ने कहा, सीएए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में और अन्य राज्यों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। राज्यों को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस कड़े कानून का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इन दलीलों पर पीठ ने कहा, आप इसके दुरुपयोग की कोई विशिष्ट घटना बताइए। इस बारे में कोई व्यापक आदेश नहीं दिया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि उनका मानना है कि यह कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस बारे में व्यापक आदेश जारी नहीं कर सकता। जब मनोहर लाल शर्मा कोर्ट से लगातार अनुरोध करते रहे कि प्रदर्शनकारियों पर इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिए, इस पर अदालत ने कहा, अगर कोई व्यक्ति हिंसा करता है या फिर गंभीर अपराध में शामिल होता है तो उस स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए। क्या सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने शर्मा से कहा कि वह यह याचिका वापस ले लें और एक संशोधित याचिका दाखिल करें जिसमें सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ रासुका का प्रयोग किए जाने की विशिष्ट घटनाएं बताएं। कोर्ट ने कहा कि वह सीएए को चुनौती देने वाली याचिकाओं में हस्तक्षेप अर्जी भी दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट की इजाजत मिलने के बाद शर्मा ने याचिका वापस ले ली।

मालूम हो कि 10 जनवरी को दिल्ली के उपराज्यपाल ने अधिसूचना जारी कर दिल्ली में 19 जनवरी से तीन महीने के लिए रासुका के प्रावधान लागू किए थे। इसमें पुलिस को किसी व्यक्ति को 12 माह तक हिरासत में रखने का अधिकार है।

संसद में विपक्षी एकजुटता की कोशिश में जुटी कांग्रेस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ सीएए-एनआरसी पर सामने आए बिखराव को संयुक्त सदन प्रबंधन रणनीति से साधने का प्रयास

नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी-एनपीआर पर विपक्षी दलों के आपसी मतभेदों के मद्देनजर कांग्रेस अब संसद सत्र के लिए इस दूरी को पाटने की पूरी कोशिश में जुट गई है। बजट सत्र में इस मुद्दे पर संसद में सरकार की मजबूत घेराबंदी करने के लिए कांग्रेस विपक्षी दलों की संयुक्त सदन प्रबंधन रणनीति को सबसे अहम मान रही है, इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सीएए-एनआरसी पर बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं होने वाले तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और शिवसेना से लेकर सपा जैसे दलों से भी संपर्क साधा जा रहा है।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और उपनेता आनंद शर्मा के साथ वरिष्ठ पार्टी रणनीतिकार अहमद पटेल संसद में विपक्षी दलों की संयुक्त रणनीति के लिए इन दलों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों ने कहा कि इन दलों के नेताओं से अब तक हुई अनौपचारिक बातचीत में संसद के दोनों सदनों में बड़े मसलों पर सरकार से दो-दो हाथ करने के लिए संयुक्त रणनीति पर किसी तरह का विरोधाभास सामने नहीं आया है। इस पर अंतिम सहमति 30 जनवरी को विपक्षी पार्टियों की प्रस्तावित बैठक में ही बनेगी।

सीएए-एनआरसी-एनपीआर पर संसद में विपक्षी दलों की एकजुटता को कांग्रेस इसलिए भी जरूरी मान रही कि बजट सत्र का पहला चरण बेहद छोटा है। ऐसे में इन मुद्दों पर सदन में सरकार की घेरेबंदी के लिए विपक्षी पार्टियों का एकजुट रहना जरूरी है ताकि सत्तापक्ष के संख्या बल को विरोध के सुर से चुनौती दी जा सके। बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है और पहला चरण 11 फरवरी को ही समाप्त हो जाएगा।

मालूम हो कि सोनिया गांधी ने 13 जनवरी को सीएए-एनआरसी-एनपीआर को लेकर विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी, लेकिन तृणमूल, सपा, बसपा ही नहीं यूपीए की घटक द्रमुक और नई साथी शिवसेना तक इसमें शामिल नहीं हुई थी। विपक्षी दलों का यह बिखराव कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था और इसके मद्देनजर ही पार्टी सियासी दूरियां पाटने में लग गई है। सीएए-एनआरसी के खिलाफ देश भर में हो रहे प्रदर्शन के साथ इसके विरोध में आंदोलन करने वालों के विरुद्ध पुलिस की सख्त कार्रवाई के मुद्दे को बजट पेश होने के बाद सबसे पहले उठाने की विपक्षी दलों की तैयारी है।

फ्रांस को साथ लेकर एफएटीएफ में पाकिस्तान को घेरेगा भारत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ पाक को एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में डालना फिलहाल संभव नहीं होगा

▶ अपने कुछ मित्र देशों की मदद से उस पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा भारत

पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के सामने दोनों देशों के बीच कारोबारी संबंध बढ़ाने की बात कही थी। उससे यह साफ हो गया था कि इस्लामाबाद पर आतंकी फंडिंग के मामले में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) का अंकुश नहीं लग सकेगा। चीन का समर्थन उसे पहले से हासिल है। अमेरिका का साथ भी मिलने से उम्मीद है कि अगले माह पेरिस में जब एफएटीएफ की बैठक होगी तो पाक को काली सूची में नहीं डाला जाएगा। भारत इस नए हालात को समझ रहा है। इसके बावजूद अपने कुछ दूसरे मित्र देशों की मदद से पाकिस्तान पर जहां तक हो सके दबाव बनाने की कोशिश करेगा।

भारत की कोशिश यही होगी कि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान ठोस व निर्णायक कदम उठाए। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर हाल के दिनों में भारत की सबसे ज्यादा मदद करने वाले फ्रांस ने एफएटीएफ में भी पूरी मदद देने का आश्वासन दिया है।

पेरिस में आगामी बैठक होने की वजह से फ्रांस के विचार का अलग महत्व है। नई दिल्ली स्थित फ्रांसीसी दूतावास के सूत्रों ने बताया कि उनके देश के लिए आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई बहुत ही अहम है। जहां तक चीन में होने वाली एफएटीएफ की बैठक का सवाल है, तो वहां जिन देशों को निगरानी सूची में रखा गया है, उसे लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सनद रहे कि चीन की राजधानी बीजिंग में होने वाली बैठक में पाक पूर्व में दिए गए मानकों को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देगा।

वैसे भारतीय पक्ष भी यह मान रहा है कि पाक को एफएटीएफ की तरफ से ब्लैक लिस्ट में डालना फिलहाल संभव नहीं होगा, लेकिन वह निगरानी सूची में बना रहेगा। इसका मतलब होगा कि पड़ोसी देश आतंकवाद को बढ़ावा देने की गतिविधियों से दूर रहेगा। एफएटीएफ के डर से पाकिस्तान सरकार ने पिछले एक वर्ष में आतंकी संगठनों के बैंकिंग सिस्टम पर न सिर्फ रोक लगाई है बल्कि कई बड़े आतंकियों को जेल में भी डाला है।

भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी मानते हैं कि अंतिम उद्देश्य यह है कि पाकिस्तान में आतंकियों व उनके संगठनों को जो भी मदद मिल रही हो वह पूरी तरह से खत्म हो। दूसरी तरफ आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान की कोशिश यह है कि वह ग्रे लिस्ट यानी निगरानी सूची से बाहर निकले। जब तक पाक ग्रे लिस्ट में रहेगा तब तक वहां बड़ी कंपनियां निवेश करने से हिचकती रहेंगी। एफएटीएफ कई देशों की सरकारों की तरफ से गठित संगठन है जो काला धन, आतंकी फंडिंग को रोकने की दिशा में काम कर रहा है।

विश्व के नक्शे पर चमकेंगी देश की 10 और झीलें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ केंद्र सरकार ने रामसर साइट के रूप में अधिसूचित किया

▶ अभी तक देश की सिर्फ 27 झीलों को ही मिला है यह दर्जा

देश की 10 और अति महत्वपूर्ण व बड़ी झीलों (वेटलैंड) को केंद्र सरकार ने रामसर साइट घोषित किया है। इनमें उत्तर प्रदेश की छह, पंजाब की तीन व महाराष्ट्र की एक झील शामिल है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही देश में अब रामसर कैटेगरी की कुल 37 झीलें हो गई हैं। सरकार ने यह घोषणा विश्व वेटलैंड दिवस से कुछ दिन पहले की है। बता दें कि दुनिया भर में दो फरवरी का दिन वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में इन झीलों को रामसर कैटेगरी में शामिल करने का प्रस्ताव किया था जिसे शुक्रवार को अधिसूचित कर दिया गया है। इसके तहत जिन 10 नई झीलों को रामसर साइट घोषित किया गया है, उनमें उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की नवाबगंज झील, इटावा जिले की सरसई नवार, गोंडा जिले की पार्वती आंगन, मैनपुरी जिले की समन, हरदोई जिले की सांडी और रायबरेली की समसपुर झील शामिल है। पंजाब की केशवपुर मनी, नांगल और ब्यास तथा महाराष्ट्र की नंदूर झील को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। दुनिया भर में मौजूदा समय में रामसर कैटेगरी की करीब 2000 झीलें हैं।

क्या है रामसर कैटेगरी : रामसर ईरान के एक शहर का नाम है जहां 1971 में वेटलैंड को बचाने को लेकर एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। कई देशों ने सम्मेलन में झीलों (वेटलैंड) को बचाने का संकल्प लिया था। तब से जिन झीलों को इस संरक्षित कैटेगरी में रखा जाता है, उन्हें रामसर कैटेगरी के नाम से जाना जाता है। इसमें किसी झील के शामिल होने को काफी अहम माना जाता हैं, क्योंकि इस कैटेगरी में आने के बाद उस झील के संरक्षण के लिए पूरी दुनिया मदद देती है। साथ ही सैलानियों की संख्या भी बढ़ जाती है।

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के इस्तेमाल पर दिया जोर

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

प्रधान न्यायाधीश ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ)के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे न्यायाधिकरण के फैसलों की सूची के प्रबंधन और निर्णय लेने में बहुत मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि एआइ को मानवीय विवेक का विकल्प नहीं बनने दिया जा सकता, जो निर्णय लेने के लिए बहुत जरूरी है। सीजेआइ ने कहा कि अदालतों में हम जिस एआइ प्रणाली को लागू करने की सोच रहे हैं, वह प्रति सेकेंड 10 लाख अक्षरों को पढ़ सकता है। इससे मुकदमों को निपटाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

अदालतों में लंबित मामले कम हुए : सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) में लंबित मामले 61 फीसद कम हुए हैं। आधिकारिक डाटा के मुताबिक, 30 जून 2017 तक 2 लाख 73 हजार 591 केस लंबित थे। 31 मार्च 2019 तक इनकी संख्या 1 लाख 5 हजार 756 रह गई।

तैयारी

सेना के 100 दिग्गजों ने इसे लेकर मोर्चा संभाला है। इस यात्रा को 'मुंडमन गंगा परिक्रमा' नाम दिया है। दावा यह है कि पहली बार इस तरह की गंगा परिक्रमा होगी

गंगा को निर्मल बनाने के अभियान में अब उतरेगी सेना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ जनजागरूकता को लेकर करेगी गंगा की पैदल परिक्रमा

▶ गोमुख से गंगा सागर तक नदी के ताजा हालात पर देगी ब्योरा

गंगा को निर्मल और अविरल बनाने की मुहिम में अब सेना भी हाथ बंटाएगी। जनजागरूकता के तहत वह गंगा की पैदल परिक्रमा करेगी जिसकी शुरुआत फिलहाल अगस्त 2020 से होगी। सेना के 100 दिग्गजों ने इसे लेकर मोर्चा संभाला है। इस यात्रा को 'मुंडमन गंगा परिक्रमा' नाम दिया है। दावा यह है कि पहली बार इस तरह की गंगा परिक्रमा होगी जो गंगा के उद्गम स्थल गोमुख से शुरू होकर गंगासागर तक और फिर गंगासागर से गोमुख तक की होगी।

मुंडमन गंगा परिक्रमा की जानकारी देते हुए अतुल्य गंगा के संस्थापक गोपाल शर्मा ने बताया कि वर्षों से हम गंगा को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लोग अभी भी इसे लेकर जागरूक नहीं हैं। ऐसे में गंगा के मैदानी क्षेत्र और आसपास बसे लोगों को इस नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को लेकर शिक्षित करने की जरूरत है। उन्हें यह बताने की जरूरत है कि अभी भी इसका हमारी अर्थव्यवस्था, जीवन शैली और आजीविका पर प्रभाव है। यही वजह है कि इस पूरी पैदल यात्रा के दौरान गंगा किनारे बसे गांव के लोगों और आसपास के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को इस पूरे अभियान में जोड़ा जाएगा। उन्हें गंगा को निर्मल बनाने के लिए जागरूक किया जाएगा। इस टीम का नेतृत्व सेना पदक विजेता लेफ्टीनेंट कर्नल हेम लोहुमी करेंगे। इस दौरान गंगा के संरक्षण को लेकर चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी पूरी दुनिया को बतलाने के लिए सेना के कर्नल मनोज केश्वर एक बाइक यात्रा पर भी निकलेंगे जो इसकी मशाल लेकर इंडिया गेट से लंदन तक जाएंगे।

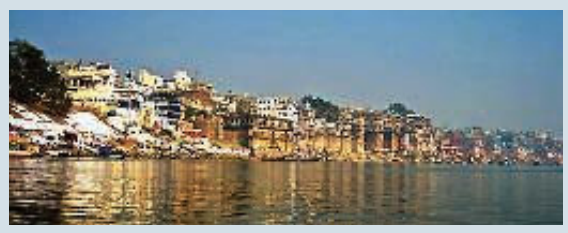

मुंडमन गंगा परिक्रमा से गंगा के साफ होने की उम्मीद जगी है। फाइल

4,700 किमी से ज्यादा लंबी होगी यह परिक्रमा : फिलहाल इस परिक्रमा का जो नक्शा तैयार किया है, उसके तहत यह यात्रा 47 सौ किमी से ज्यादा लंबी होगी जो करीब सात महीने चलेगी। इसके साथ ही यात्रा के कुछ नियम भी तय किए गए हैं, जिसमें नदी तट से अधिकतम एक योजन यानी 13 किमी की दूरी से होकर ही यह गुजरेगी। साथ ही 24 घंटे में एक बार गंगा का दर्शन करना आवश्यक होगा। वहीं, परिक्रमा करने वाले यात्री को नदी के अंतिम छोर पर ही नदी को पार करने की अनुमति होगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि किसी की जान को खतरा न हो।

20वीं सदी के आखिरी दशक में विदेश में छिपानी शुरू की थी काली कमाई

प्रथम पृष्ठ से आगे

इस ग्रुप ने 20वीं सदी के आखिरी दशक से ही टैक्स हैवेन समझे जाने वाले देशों में ट्रस्ट बना कर अपनी काली कमाई को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया था। ये ट्रस्ट इस तरह से विदेशों में पैसा जमा कराते हैं कि इसके असली मालिक या प्रमोटर का पता दशकों तक नहीं लगता है। कई देशों में निवेश होने और असली प्रमोटर को छिपाने के कई रास्ते आजमाए गए हैं। ग्रुप के प्रमुख प्रमोटर ने अपने एक करीबी रिश्तेदार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस ट्रस्ट मुखिया बना रखा है। वित्त मंत्रालय के अफसरों के मुताबिक अब इस समूह के काले कारनामों पर से पर्दा हट गया है। कंपनी का ब्रिटेन में एक होटल है और कई अन्य परिसंपत्तियों में भी ग्रुप ने निवेश किया है। यूएई में भी इसी तरह का निवेश किया गया है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी